>

Title: The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding the Government Business for the remaining part of the 3rd session of the 15th Lok sabha.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration of Resolution seeking approval to constitute a new Railway Convention Committee (15th Lok Sabha) for determination of 'Rate of Dividend payable by the Railways to the General Revenues and other ancillary matters'.
3. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2009-10.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 2009.
5. Consideration and passing of the following Bills:-
   (a) The Competition (Amendment) Bill, 2009 to replace an Ordinance;
   (b) The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2009;
   (c) The National Green Tribunal Bill, 2009;
   (d) The State Bank of Sourashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009; and
   (e) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2009.
6. Consideration and passing of the Legal Metrology Bill, 2009, as passed by Rajya Sabha.
7. Consideration and passing of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2005, after it is passed by Rajya Sabha.
8. Consideration and passing of the Civil Defence (Amendment) Bill, 2009.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए।

1. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत मानसी जंक्शन काफी महत्वपूर्ण है। मानसी जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर उसे मॉडल स्टेशन बनाया जाए।

2. बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया जिला में एन.एच.-107 के पिरनगरा से माली के बीच बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में बने पुराने हूम पाइप कलभर्ट के स्थान पर उच्च स्तरीय ब्रिज एवं पथ का उच्चिकरण कराया जाए।

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों के शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु कार्य।

2. मेरे प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में साई नदी में प्रदूषण को दूर करने हेतु एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा का कार्य।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would request you to include the following items in the next week's agenda:-

1. Kanhangad-Panathur Railway Line should be included in the next Railway Budget itself.
2. Endosulphan, a chemical pesticide which is dangerous to the human health, should be banned.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, the following items may be included in next week's agenda:-

1. The preparation of Commonwealth Games as it is going to be held in the year 2010 which will consolidate the position of India in the Comity of Nations.
2. Fund for Health Mela organized by the Ministry of Health in each Lok Sabha constituency should be enhanced in view of the current pricing scenario.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I would like to request you to kindly include the following subjects in next week's agenda:

1. Adverse effects of BT cotton is a matter of deep concern for all the concerned, particularly the farmers. Therefore, the long pending Seed Bill be brought before the House for discussion.
2. Water Management in the country is urgently needed particularly in view of the Global Warming and its impact on the country.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने की व्यवस्था की जाये।

(क) "कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वÂाऩ 1990-91 में कोल कंपनियों के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए कोल ट्रैंक रोड नामक सम्पर्क सड़क की जर्जर स्थिति की समीक्षा और झारखंड में निर्मित उक्त सड़कों और पुलों के निर्माण और जीर्णोद्धार की आवश्यकता।"

(ख) "सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड द्वारा वÂर्ष 1980 में चरही क्षेत्र के हजारीबाग जिला के पचमों पंचायत के किसानों को कोयला खदान खोलने हेतु अधिगृहीत भूमि को टिस्को कम्पनी को "लीज डीड" के आधार पर बिक्री की गयी/बिक्री की जा रही भूमि पर अविलम्ब रोक लगाने की आवश्यकता अथवा उक्त भूमि के किसानों के माध्यम से बिक्री कराने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता।"

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा हेतु जोड़ने की अनुमति दें।

(1) तेलंगाना पृथक राज्य से संबंधित खबर से देश में राज्यों के पुनर्गठन एवं नए राज्यों के गठन को लेकर संसद में सभी माननीय सांसदों के विचार जानने हेतु खुली व लम्बी चर्चा करायी जाये।

(2) योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवÂाावय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन औ र इस महीने होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक स्थगति होने से देश के विकास पर होने वाले प्रभावों के बारे में संसद में खुली व लम्बी बहस करायी जाये।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को शामिल कराने का कÂट करें।

1. बिहार के रोहतास तथा औरंगाबाद नक्सल प्रभावित जिलों में औरंगाबाद पटना एनएच 98 से नासरीगंज-विक्रमगंज पथ पर सोन नदी पर पुल बनाने का कार्य।

2. हमारे संसदीय क्षेत्र कारकोट के जिले रोहतास तथा औरंगाबाद एवं कैमूर जिले में जहां अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये-

1. राजधानी दिल्ली में विशेषकर उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले को राÂष्ट्रीय सम विकास योजना में सम्मिलिति किए जाने के बारे में।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये।

1. रेल मंत्रालय रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत भागीदारी मांगता है। राज्यों के सीमित संसाधनों के देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार कर सभी आरओबी का निर्माण रेल मंत्रालय अपने संसाधनों/निधियों से करे।

2. देश के जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष परियोजना तथा इन क्षेत्रों में विकास हेतु धनराशि आवंटन की घोषणा सरकार करे।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, before we take up the Calling Attention, we have a motion and introduction of a Bill to be taken up. If the House agrees, we take up Calling Attention after that.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, please.